

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून : दिनांक 16 नवम्बर, 2015

विषय:- नगरपालिका परिषद, बाजपुर को अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 484/V-श0वि0-06-195(सा0)/05टी0सी0, दिनांक 06.03.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, बाजपुर के अन्तर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ₹374.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या: 801/V-श0वि0-06-166(सा0)/03टी0सी0, दिनांक 29.03.2006 के द्वारा ₹187.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बाजपुर के पत्रांक-130/अवशेष राशि/15, दिनांक 10.07.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा से हुयी बचत ₹2.45 लाख का समायोजन करने के उपरान्त स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹38.43 लाख (रूपये अड़तीस लाख तेतालीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उक्त धनराशि कुल ₹38.43 लाख (रूपये अड़तीस लाख तेतालीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, बाजपुर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ii) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (iii) निर्माण कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (v) कार्य के मध्य अथवा बाद में इसकी गुणवत्ता की चैकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराकर आख्या यथासमय शासन को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका व्यय अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
- (vi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

- (viii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- (x) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (xi) प्रश्नगत निर्माण योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में सचिव, शहरी विकास विभाग, की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 03.09.2015 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रश्नगत योजना हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष रु. 76.85 लाख की धनराशि दो किस्तों में नगर निकाय को उपलब्ध निर्गत की जानी है और शेष धनराशि का वहन नगर निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा एवं निर्माण कार्य मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही पूर्ण कराया जायेगा। तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (xii) विषयकपेश मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (xiii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (xiv) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- (xv) पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 06.03.2006 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- /XXVII(2)/2015, दिनांक नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न- एलॉटमेन्ट आईडी0 S.15.1.1.3.0084

भवदीय,
(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव।

संख्या-1448(1)/IV(2)-शा0वि0-2015, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।

4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, बाजपुर को सूचनार्थ एवं सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.09.2015 को आहूत बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।